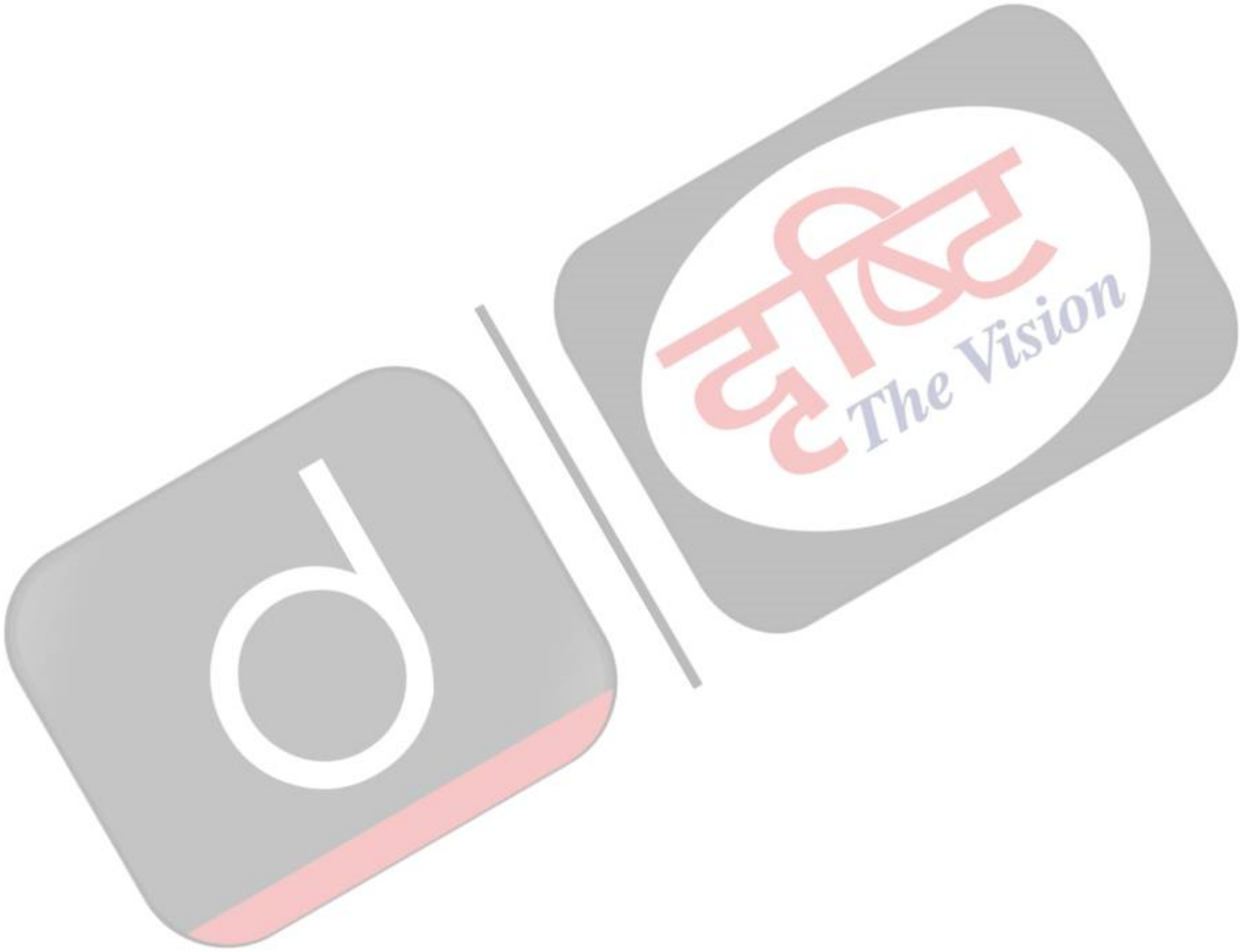


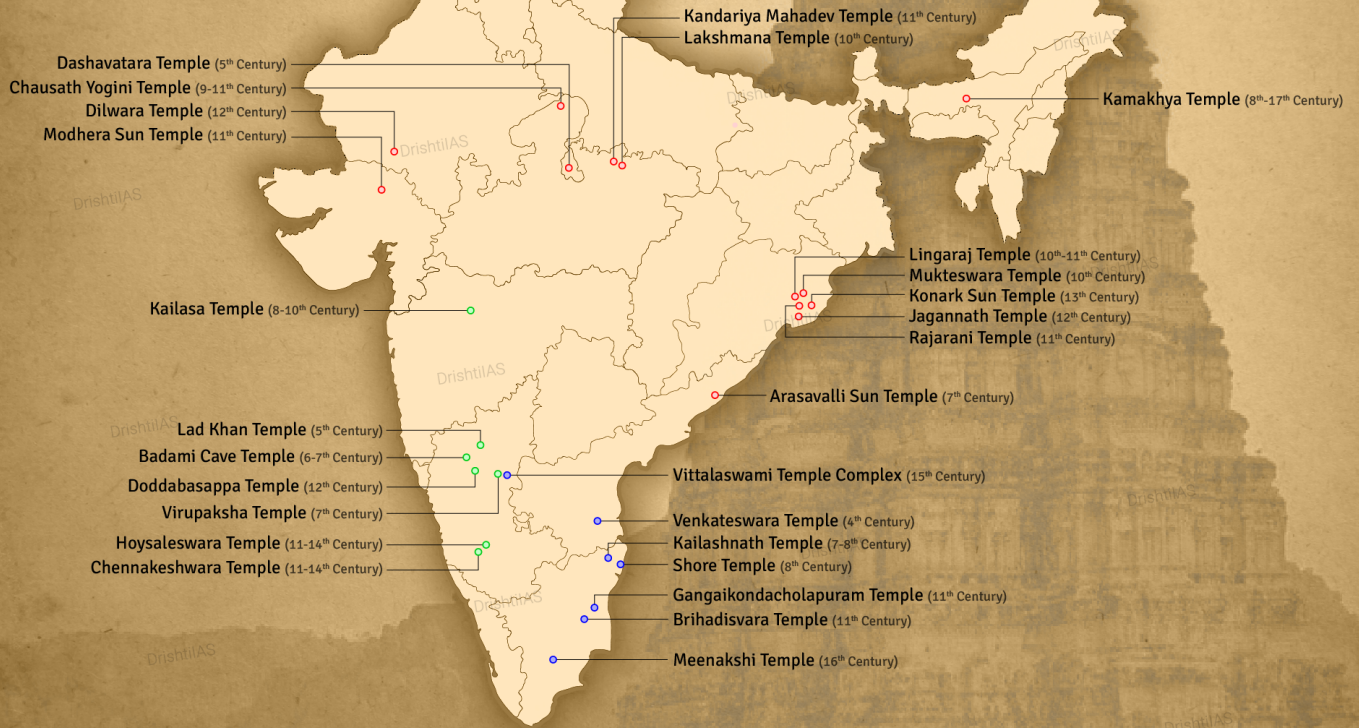


भारत में मंदिर

//



भारत में मंदिर



नागर शैली



द्विड शैली



वैसर शैली

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद

प्रलिस के ललल:

अनुच्छेद 131, सर्वोच्च न्यायालय, सरकारल आयोग, संवधलन कल अनुच्छेद 263 ।

मेन्स के ललल:

भलरत में अंतर-रलज्यीय वलवलद महलरलषुटर-करुनलटक सीमल वलवलद और आगे की रलह ।

चरुल में करुल?

महलरलषुटर और करुनलटक के बीच सीमल वलवलद की गंभीरतल को देखते हुए दोनू रलज्यू ने वलवलद को हल करने के ललल कलनूनी लडलई कल समरुथन करने हेतु एक सरुवसममत प्रसुतलव पलरलत कलल है ।

महलरलषुटर-करुनलटक सीमल वलवलद:

परचलल:

- उतुतरी करुनलटक में बेलगलवी, कलरवलर और नपलनी को लेकर सीमल संबुधी वलवलद कलफी पुरलनल है ।
- वरुष 1956 के रलज्य पुनरुगठन अधनलललम के अनुसार, जब रलज्य की सीमलओ को भलषलयी आधलर पर नरुधलरलत कलल गल, तब बेलगलवी पूरुववरुती मैसूर रलज्य कल हसलसल बन गल ।
 - यह अधनलललम वरुष 1953 में नललुकुत नुलललमूरुतल फलजल अली आयोग के नषलकरुषू पर आधलरलत थल और उनहूने दो वरुष बलद अपनी रपुलरुट प्रसुतुत की थी ।
- महलरलषुटर कल दलवल है कल बेलगलवी के कुषु हसलसे, जहलू मरलठी प्रमुख भलषल है, महलरलषुटर के अंतरुगत रहने चलहलल ।
- अकतुबर 1966 में केंदर ने महलरलषुटर, करुनलटक और केरल में सीमल वलवलद को हल करने के ललल भलरत के पूरुव मुख्य नुललललधीश मेहर चंद महलजन के नेतुतुत में महलजन आयोग की सुथलपनल की ।
- इस आयोग ने सफलरलश की कल बेलगलम और 247 गलू करुनलटक के अंतरुगत रहू । महलरलषुटर ने इस रपुलरुट को खलरलज कर दलल और वरुष 2004 में सर्वोच्च नुललललम कल रुख कलल ।

महलरलषुटर के दलवे कल आधलर:

- महलरलषुटर कल अपनी सीमल के पुनः समललोजन कल दलवल सलमीपुय, सलपेकुष भलषलयी बहुमत और लुगू की इकुषल के आधलर पर थल । बेलगलवी और आसपलस के कुषेतुू में मरलठी भलषी लुगू तथल भलषलयी एकरुपतल के आधलर पर दलवे कल मुख्य कलरण कलरवलर एवं सुपल कुषेतुू में मरलठी की बेली के रूड में उदुधुत भलषल कूंकणी कल प्रलुग है ।
- इसकल तरुक इस वलललर पर केंदरलत थल कल गलणनल समुदललू के आधलर पर हुनी चलहलल, और इसने प्रतुयेक गलू में भलषलयी नलललसललू की संखुल/आबलदी को सूचीबदुध कलल ।
- महलरलषुटर ने इस ऐतलहलसकल तथुय की ओर भी इशलरल कलल कल इन मरलठी भलषी कुषेतुू के रलजसुव अभललख भी मरलठी में ही हुते हैं ।

करुनलटक की सुथलतल:

- करुनलटक ने तरुक दलल है कल रलज्य पुनरुगठन अधनलललम के अनुसार सीमलओ कल समझूतल अंतमल है ।
- रलज्य की सीमल न तु असुथलली थी और न ही ललली । रलज्य कल तरुक है कललह मुदुदल उन सीमल मुदुदू को फरल से खल देगल जनल पर अधनलललम के तहत वलललर नही कलल गलल है, अतः ऐसी मलंग की अनुमतल नही दी जलनी चलहलल ।

समसुल के समलधलन के ललल उतलए गए कदम:

- अंतर-रलज्यीय वलवलदू को अकुसर दोनू पकुषू के सहलुग से हल करने कल प्रललस कलल जलतल है, जसलमें केंदर एक सुूतरधलर यल तटसुथ मधुयसुथ के रूड में कलम करुतल है ।
- यदु मुदुदू को सुूहलरुदपूरुण ढंग से हल कलल जलतल है, तु संसद रलज्य की सीमलओ को बदलने के ललल कलनून लल सकुती है, जैसे बहलर-उतुतर प्ररदेश (सीमलओ कल परवलरुतन) अधनलललम 1968 और हरललणल-उतुतर प्ररदेश (सीमलओ कल परवलरुतन) अधनलललम 1979 ।
- बेलगलवी मलमले में केंदरीय गृह मंतुूरी अमतल शलह ने दोनू रलज्यू के मुखुयमंतुूरललू से मुललकलत की ओर उनहू सभी सीमल मुदुदू को हल करने के ललल प्रतुयेक पकुष के तीन मंतुूरललू वलली छह सदसुयीय टीम बनलने के ललल कलल ।

अनुय उडलबुध तरुीके:

नुलललकल नललरुण:

- सरुवोच्च नुललललम अपने मूल कुषेतुूरलधकलर के तहत रलज्यू के बीच वलवलदू कल नपलटलरल करुतल है ।
- संवधलन के अनुच्छेद 131 के अनुसार, भलरत सरकलर और कसल रलज्य के बीच यल दल यल दल से अधकल रलज्यू के बीच कसल भी प्रकलर के वलवलद को सुलझलनल सरुवोच्च नुललललम कल मूल कुषेतुूरलधकलर है ।

अंतर-रलज्यीय परषलद:

- संवधान का अनुच्छेद 263 **राष्ट्रपति** को राज्यों के बीच विवादों के समाधान के लिये अंतर-राज्यीय परिषद गठित करने की शक्ति देता है।
- परिषद की परिकल्पना राज्यों और केंद्र के बीच चर्चा के लिये एक मंच के रूप में की गई है।
 - वर्ष 1988 में **सरकारिया आयोग** ने सुझाव दिया कि परिषद को एक स्थायी निकाय के रूप में गठित किया जाना चाहिये तथा वर्ष 1990 में यह राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से अस्तित्व में आया।

अन्य अंतरराज्यीय विवाद:

असम-अरुणाचल प्रदेश:	■ असम और अरुणाचल प्रदेश 804.10 किमी. की अंतर-राज्यीय सीमा साझा करते हैं। ■ वर्ष 1987 में बनाए गए अरुणाचल प्रदेश राज्य का दावा है कि पारंपरिक रूप से इसके निवासियों की कुछ भूमि असम को दे दी गई है। ■ एक त्रिपक्षीय समिति ने सफाई की थी कि कुछ क्षेत्रों को असम से अरुणाचल प्रदेश में स्थानांतरित किया जाए। इस मुद्दे को लेकर दोनों राज्य न्यायालय की शरण में हैं।
असम-मजोरम:	■ मजोरम अलग केंद्रशासित प्रदेश बनने से पहले असम का एक जिला हुआ करता था जो बाद में अलग राज्य बना। ■ मजोरम की सीमा असम के कछार, हैलाकांडी और करीमगंज जिलों से लगती है। ■ समय के साथ सीमांकन को लेकर दोनों राज्यों की अलग-अलग धारणाएँ बनने लगीं। ■ मजोरम चाहता है कि यह बाहरी प्रभाव से आदिवासियों की रक्षा के लिये वर्ष 1875 में अधिसूचित एक आंतरिक रेखा के साथ हो, जो मजोरम को उनकी ऐतिहासिक मातृभूमि का हिसा लगाता है, असम का मानना है कि सीमा का निर्धारण बाद में तैयार की गई जिला सीमाओं के अनुसार किया जाए।
असम-नगालैंड:	■ वर्ष 1963 में नगालैंड के गठन के बाद से ही दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद चल रहा है। ■ दोनों राज्य असम के गोलाघाट जिले के मैदानी इलाकों के निकट एक छोटे से गाँव मेरापानी पर अपना दावा करते हैं। ■ वर्ष 1960 के दशक से इस क्षेत्र में हसिक झड़पों की खबरें आती रही हैं।
असम-मेघालय:	■ मेघालय ने करीब एक दर्जन क्षेत्रों की पहचान की है जहाँ राज्य की सीमाओं को लेकर असम के साथ उसका विवाद है।
हरियाणा-हिमाचल प्रदेश:	■ दो उत्तरी राज्यों (हरियाणा-हिमाचल प्रदेश) में परवाणू क्षेत्र को लेकर सीमा विवाद है, जो हरियाणा के पंचकुला जिले के समीप स्थित है। ■ हरियाणा ने इस क्षेत्र की ज़मीन के काफी बड़े हिस्से पर अपना दावा किया है और हिमाचल प्रदेश पर हरियाणा के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों पर कब्ज़ा करने का आरोप लगाया है।
लद्दाख-हिमाचल प्रदेश:	■ लद्दाख और हिमाचल प्रदेश दोनों केंद्रशासित प्रदेश सरचू क्षेत्र पर अपना दावा करते हैं, जो लेह-मनाली राजमार्ग से यात्रा करने वालों के लिये एक प्रमुख पड़ाव बंद है। ■ यह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा लद्दाख के लेह जिले के बीच स्थित है।

आगे की राह

- राज्यों के बीच सीमा विवादों को वास्तविक सीमा स्थानों के उपग्रह मानचित्रण का उपयोग करके सुलझाया जा सकता है।
- अंतर-राज्यीय परिषद को पुनर्जीवित करना अंतर-राज्यीय विवाद के समाधान का एक विकल्प हो सकता है।
 - संवधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतर-राज्यीय परिषद से विवादों की जाँच और सलाह देने, सभी राज्यों के लिये सामान्य विषयों पर चर्चा करने तथा बेहतर नीति समन्वय हेतु सफाई करने की अपेक्षा की जाती है।
- इसी तरह सामाजिक और आर्थिक नियोजन, सीमा विवाद, अंतर-राज्यीय परिवहन आदि से संबंधित मुद्दों पर प्रत्येक क्षेत्र में राज्यों के लिये सामान्य चर्चा के मामलों पर चर्चा करने हेतु **क्षेत्रीय परिषदों** को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है।
- भारत अनेकता में एकता का प्रतीक है। हालाँकि इस एकता को और मज़बूत करने के लिये केंद्र व राज्य सरकारों दोनों को **सहकारी संघवाद** के लोकाचार को आत्मसात करने की आवश्यकता है।

प्रश्न. केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का फैसला करने के लिये भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्त किसके अंतर्गत है? (2014)

- (a) सलाहकार क्षेत्राधिकार
- (b) अपीलीय क्षेत्राधिकार
- (c) मूल अधिकार क्षेत्र
- (d) रटि क्षेत्राधिकार

उत्तर: (c)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2022

प्रलिस के लिये:

जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2022, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1991 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

मेन्स के लिये:

सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, कुछ अपराधों का गैर-अपराधीकरण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने संसद में जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2022 पेश किया।

- इसका उद्देश्य 42 विधानों में 183 अपराधों का "गैर-अपराधीकरण" करना है और भारत में रहने तथा [ईज ऑफ़ ड्रिग बिजनेस](#) को बढ़ावा देना है।
- अधिनियम द्वारा संशोधित किये गए कुछ अधिनियमों में शामिल हैं: [भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898](#); [पर्यावरण \(संरक्षण\) अधिनियम, 1986](#); [सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1991](#) और [सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000](#)।

प्रमुख बिंदु

- कुछ अपराधों का गैर-अपराधीकरण:
 - अधिनियम के तहत कुछ अधिनियमों में कारावास की सज़ा वाले कई अपराधों को केवल अर्थ दंड लगाकर अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है।
 - उदाहरण के लिये:
 - कृषि उपज (ग्रेडिंग और मार्केटिंग) अधिनियम, 1937 के तहत नकली ग्रेड पदनाम चहिन तीन वर्ष तक के कारावास और पाँच हजार रुपए तक के जुर्माने के साथ दंडनीय है। ग्रेड पदनाम चहिन वर्ष 1937 अधिनियम के तहत वस्तु की गुणवत्ता को दर्शाता है।
 - यह अधिनियम इसके स्थान पर आठ लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान करता है।
 - सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत एक वैध अनुबंध के उल्लंघन में व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करने पर तीन साल तक की कैद या पाँच लाख रुपए तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।
 - यह अधिनियम इसके स्थान पर 25 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान करता है।
 - उदाहरण के लिये पेटेंट अधिनियम, 1970 के तहत भारत में पेटेंट के रूप में गलत प्रतिनिधित्व वाली वस्तु बेचने वाले व्यक्ति पर एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
 - कुछ अधिनियमों में दंड के बजाय जुर्माना लगाकर अपराधमुक्त कर दिया गया है।
 - यह अधिनियम अर्थदंड (फाइन) के स्थान पर जुर्माने (पेनाल्टी) का प्रावधान करता है, जो दस लाख रुपए तक हो सकता है। दावा जारी रखने की स्थिति में प्रतिदिन एक हजार रुपए का अतिरिक्त जुर्माना देना होगा।
 - अर्थदंड और जुर्माने में संशोधन:
 - यह अधिनियम नरिदष्टि अधिनियमों के तहत विभिन्न अपराधों के लिये अर्थदंड और जुर्माने में वृद्धि करता है।
 - इसके अलावा इन अर्थदंड और जुर्माने को प्रतितीन वर्ष में न्यूनतम राशि के 10% तक बढ़ाया जाएगा।
 - नरिणायक अधिकारियों की नयुक्ति:

- वधियक के अनुसार, **केंद्र सरकार दंड नरिधारति करने के उद्देश्य से एक या एक से अधिक न्यायनरिणयन अधिकारियों की नयुक्त कर सकती है।** नरिणायक अधिकारी: (i) व्यक्तियों को साक्ष्य के लिये समन भेज सकते हैं और (ii) संबंधित अधिनियमों के उल्लंघन की जाँच कर सकते हैं।

■ अपीलीय तंत्र:

- वधियक न्यायनरिणयन अधिकारी द्वारा पारित **आदेश से परेशान किसी भी व्यक्ति के लिये अपीलीय तंत्र को भी नरिदषिट करता है।**
 - उदाहरण के लिये पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत आदेश के 60 दिनों के भीतर राष्ट्रीय हरति अधिकरण में अपील दायर की जा सकती है।

वधियक को लाने के पीछे उद्देश्य:

■ आपराधिक मामलों में वृद्धि:

- दशकों से वधिवित्ता इस बात से चिंतित हैं कि आपराधिक कानून सदिधांतहीन रूप से विकसित हुआ है।
- राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के अनुसार, 4.3 करोड़ लंबित मामलों में से लगभग 3.2 करोड़ मामले आपराधिक कार्यवाही से संबंधित हैं।

■ राजनीतिक उद्देश्य:

- गलत आचरण हेतु दंडित करने के विपरीत **अपराधीकरण अक्सर सरकारों के लिये एक मज़बूत छविपेश करने का उपकरण बन जाता है।**
- सरकारें इस तरह के फैसलों का समर्थन बहुत कम करती हैं। इस घटना को वदिवानों द्वारा "अतिअपराधीकरण" कहा गया है।

■ जेलों में कक्षमता से अधिक कैदी:

- **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो** के वर्ष 2021 के आँकड़ों के अनुसार, कुल 4.25 लाख की क्षमता वाली जेलों में 5.54 लाख कैदी थे।

वधियक का दायरा:

- वधियक '**अर्द्ध-गैरअपराधीकरण**' (Quasi-Decriminalisation) को भी अपने दायरे में ला सकता है।
- ऑब्ज़र्वर रसिर्च फाउंडेशन द्वारा जारी रिपोर्ट जेल्ड फॉर ड्रूंग बज़िनेस के अनुसार, भारत में कुल 843 आर्थिक वधिनो, नयिमों तथा वनियिमों में 26,134 से अधिक कारावास संबंधी उपखंड हैं जो भारत में व्यवसायों एवं आर्थिक गतिविधियों को वनियिमित करते हैं।
 - इस आलोक में वधियक के तहत गैर-अपराध की श्रेणी में शामिल किये गए अपराधों की संख्या केवल भारत के नयिमक ढाँचे में अल्प मात्रा में गरिवट को दर्शाती है।
- न केवल व्यापार सुगमता बल्कि उन सभी बुराइयों, जो हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली को प्रभावित करती हैं, के दृष्टिकोण से भी 'गैर-अपराधीकरण' के लिये वधिार किये जाने वाले वनियिमक अपराधों की प्राथमिकता नरिधारति करने की आवश्यकता है।
- यह वधियक सरकार की इस सहमति के अनुरूप है कि गैर-अपराधीकरण नयिमक क्षेत्र तक सीमति होना चाहिये।

स्रोत: द हट्टि

यूक्रेन शांति सूत्र

प्रलिमिस के लिये :

G-20, G-7, शांति सूत्र

मेन्स के लिये :

यूक्रेन शांति सूत्र और इसके प्रतिविश्व की प्रतिक्रिया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने भारत की **G-20 अध्यक्षता** और यूक्रेन की "**10 सूत्री शांति योजना**" पर चर्चा करने के लिये यूक्रेन के राष्ट्रपति से वार्ता की।

- दसिंबर 2022 की शुरुआत में यूक्रेन ने **G-7 देशों के नेताओं** से सर्दियों में अपने वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन के वधिार का समर्थन करने का आग्रह किया, जो "संपूर्ण रूप से या वशिष रूप से कुछ वशिषिट बट्टिओं" पर शांति योजना पर ध्यान केंद्रित करेगा।

यूक्रेन की 10 सूत्री शांति योजना:

- यूक्रेन ने पहली बार 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह के नवंबर 2022 शिखर सम्मेलन में अपने शांति सूत्र की घोषणा की थी। योजना के अंतर्गत नमिन्लखित मांगें हैं:
 - वकिरिण और **परमाणु सुरक्षा**: यूक्रेन में यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र ज़ापोरिज़िया के आसपास सुरक्षा बहाल करने पर ध्यान केंद्रित करना, जो अब रूस के कब्जे में है।
 - **खाद्य सुरक्षा**: इसमें दुनिया के सबसे गरीब देशों को यूक्रेन से अनाज नरियात और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है।
 - **ऊर्जा सुरक्षा**: रूसी ऊर्जा संसाधनों पर मूल्य प्रतर्बिधों को लेकर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ यूक्रेन को उसके वदियुत बुनयिदी ढाँचे, जिसका आधा हसिसा **रूसी आक्रमण** से क्षतग्रिस्त हो गया है, को बहाल करने में सहायता करना।
 - युद्ध बंदियों और रूस भेजे गए बच्चों सहित सभी बंदियों एवं नरिवासतियों की रहिआई।
 - यूक्रेन की क्षेत्तीय अखंडता को बहाल करना और **संयुक्त राष्ट्र** (United Nations) चार्टर के अनुसार रूस द्वारा इसकी पुष्टि करना।
 - रूसी सैनिकों की वापसी और शत्रुता की समाप्ति, रूस के साथ यूक्रेन की राज्य सीमाओं की बहाली।
 - न्याय सहित, रूसी युद्ध अपराधों के खिलाफ मुकदमा चलाने हेतु एक वशिष न्यायाधकिरण की स्थापना।
 - जल उपचार सुवधियों को बहाल करने पर ध्यान देने के साथ पर्यावरण की सुरक्षा।
 - यूक्रेन के लिये गारंटी सहित यूरो-अटलांटिक क्षेत्त्र में संघर्ष की रोकथाम और सुरक्षा ढाँचा का नरिमाण।
 - युद्ध की समाप्ति की पुष्टि, जिसमें शामिल पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज।

शांति सूत्र के प्रतविश्व की प्रतकिरिया:

- रूस ने यूक्रेन के शांतिप्रस्ताव को खारज़ि कर दिया और पुनः बताया कि वह सैनिकों द्वारा कब्ज़ा किये गए यूक्रेन के लगभग पाँचवें हसिसे (1/5वें) के आसपास के क्षेत्त्र को नहीं छोड़ेगा।
- यूक्रेन की सेना को पश्चिमी देशों द्वारा वाशिगटन के नेतृत्त्व में अरबों डॉलर का सहयोग किये गया साथ ही ये राष्ट्र यूक्रेन के वदियुत बुनयिदी ढाँचे के वकिस हेतु मदद कर रहे हैं।
 - लेकिन यूक्रेन की शांति योजना और प्रस्तावित शांति शिखर सम्मेलन की प्रतकिरिया के संदर्भ में काफी देश अधकि सतर्क रहे हैं।
- G7 नेताओं ने बताया कि वे "संयुक्त राष्ट्र चार्टर में नहिनि अपने अधकिारों के अनुरूप" यूक्रेन में शांति लाने के लिये प्रतबिद्ध हैं।

स्रोत: द हट्टि

RTI जवाबदेही रिपोर्ट कार्ड

प्रलिमिन्स के लिये:

सूचना का अधकिार (RTI) अधनियिम, केंद्रीय सूचना आयोग, SIC, सतर्क नागरिक संगठन।

मेन्स के लिये:

सूचना का अधकिार (RTI) अधनियिम, पारदर्शिता और जवाबदेही।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सतर्क नागरिक संगठन (SNS) ने **सूचना का अधकिार (Right to Information- RTI) अधनियिम 2021-22** के तहत जवाबदेही रिपोर्ट कार्ड जारी किये हैं, जो दर्शाता है कि तमलिनाडु RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है, जिसकी नपिटान दर 14% है।

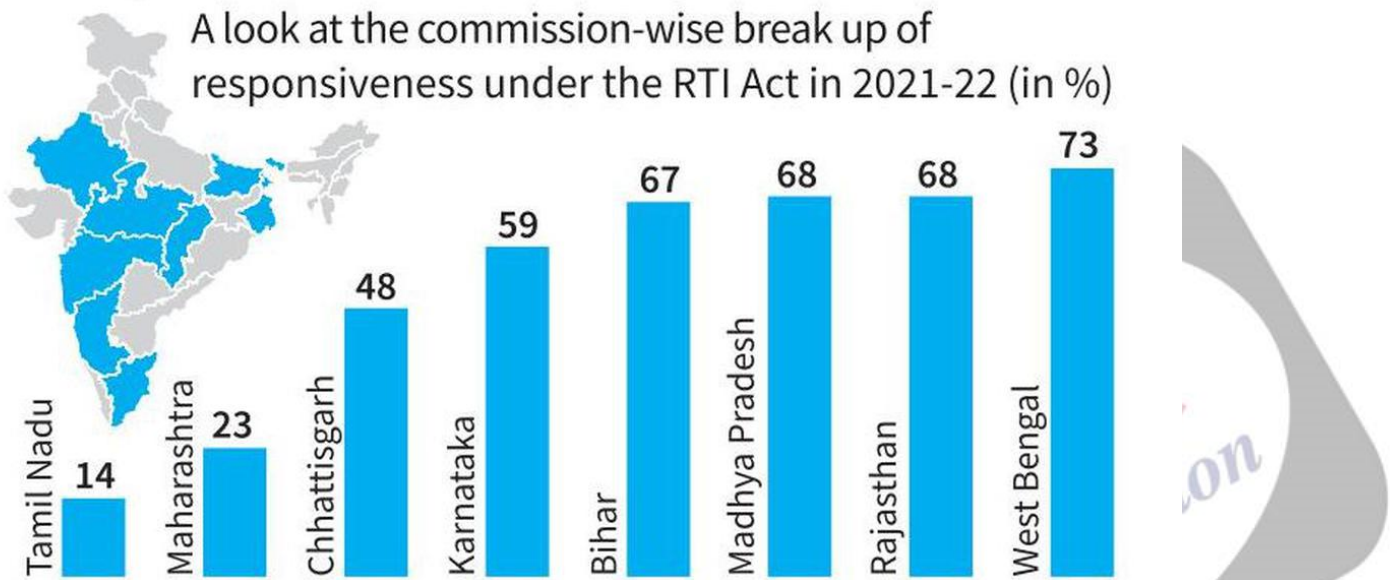
प्रमुख बट्टि

- महाराष्ट्र RTI जवाबदेही में दूसरा सबसे खराब स्थितिवाला राज्य है, जिसकी नपिटान दर 23% है।
- इस मूल्यांकन के भाग के रूप में दायर RTI आवेदनों के जवाब में केवल 10 सूचना आयुक्तों ने पूरी जानकारी प्रदान की। इनमें **आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्य सकिक्मि, नगालैंड और त्रिपुरा** शामिल थे।
- बिहार राज्य सूचना आयुक्त (State Information Commissioner- SIC), जो वर्ष 2020 और 2021 में प्रकाशित आकलन के लिये RTI अधनियिम के तहत कोई भी जानकारी प्रदान करने में वफिल रहा था, ने अपने प्रदर्शन में काफी सुधार किये और इसकी नपिटान दर 67% है।

- देश भर में बड़ी संख्या में सूचना आयुक्तों ने बना कोई आदेश पारति कयि मामले वापस कर दयि थे ।
 - उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश ने प्राप्त अपीलों या शिकायतों में से लगभग 40% को वापस कर दिया ।
 - 18 सूचना आयुक्तों में से 11 ने बना कोई आदेश पारति कयि अपील या शिकायत वापस कर दी थी ।
- सूचना आयुक्तों के संदर्भ में प्रतिआयुक्त नपिटान की दर बेहद कम है ।
 - उदाहरण के लिये पश्चिम बंगाल के SIC के पास मामलों की वार्षिक औसत नपिटान दर प्रतिआयुक्त 222 थी, जिसका अर्थ है कि प्रतिआयुक्त आयुक्त प्रभावी रूप से एक दिन में मुश्किल से एक मामले का नपिटान कर रहा था । वैसे लंबित मामलों की संख्या 10,000 से भी अधिक थी ।
- सभी 29 सूचना आयुक्तों में से केवल केंद्रीय सूचना आयुक्त ने एक वर्ष में प्रतिआयुक्त द्वारा नपिटाए जाने वाली अपीलों अथवा शिकायतों की संख्या के संबंध में एक मानक अपनाया है ।

Report card

A look at the commission-wise break up of responsiveness under the RTI Act in 2021-22 (in %)



सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम:

- परिचय:
 - सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 सरकारी सूचना के लिये नागरिकों के प्रश्नों के प्रति समयबद्ध जवाबदेही अनिवार्य बनाता है ।
 - सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को रोकना तथा वास्तविक अर्थों में हमारे लोकतंत्र का लोगों के लिये कार्य करना है ।
- सूचना का अधिकार (संशोधन) विधियक, 2019
 - इसमें प्रावधान किया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त और एक सूचना आयुक्त (केंद्र के साथ-साथ राज्यों के) केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिये पद धारण करेंगे । इस संशोधन से पहले इनका कार्यकाल 5 साल के लिये तय किया गया था ।
 - इसमें प्रावधान किया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त (केंद्र के साथ-साथ राज्यों के) के वेतन, भत्ते तथा अन्य सेवा संबंधी शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी ।
 - इस संशोधन से पूर्व, मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा संबंधी शर्तें मुख्य चुनाव आयुक्त के समान थीं एवं सूचना आयुक्त के वेतन, भत्ते तथा अन्य सेवा संबंधी शर्तें एक चुनाव आयुक्त (राज्यों के मामले में राज्य चुनाव आयुक्त) के समान थीं ।
 - इसने मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त के लिये पेंशन या किसी अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के कारण वेतन कटौती से संबंधित खंडों को समाप्त कर दिया, जो उन्हें उनकी सरकारी नौकरी के लिये प्राप्त हुए थे ।
 - RTI (संशोधन) अधिनियम, 2019 की आलोचना कानून को कमजोर करने और केंद्र सरकार को अधिक शक्तियाँ देने के आधार पर की गई थी ।
- कार्यान्वयन में समस्याएँ:
 - सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर में गैर-अनुपालन ।
 - नागरिकों के प्रति लोक सूचना अधिकारियों (Public Information Officers-PIOs) का शत्रुतापूर्ण रवैया और सूचना छपाने के लिये सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के प्रावधानों की गलत व्याख्या करना ।
 - जनहिंसा और नजिता के अधिकार के संबंध में स्पष्टता का अभाव ।
 - राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव और खराब बुनियादी ढाँचा ।
 - सार्वजनिक महत्त्व के आवश्यक मामलों पर सक्रिय नागरिकों द्वारा कयि गए सूचना अनुरोधों की अस्वीकृति ।
 - RTI कार्यकर्ताओं और आवेदकों की आवाज़ दबाने के लिये उनके खिलाफ हमलों एवं धमकियों जैसे अन्य साधन ।

केंद्रीय सूचना आयोग (CIC):

- **स्थापना:** CIC की स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम (2005) के प्रावधानों के तहत वर्ष 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। यह संवैधानिक निकाय नहीं है।
- **सदस्य:** इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और दस से अधिक सूचना आयुक्त नहीं हो सकते हैं।
- **नियुक्ति:** उन्हें राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सफारिश पर नियुक्त किया जाता है जिसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, लोकसभा में वपिक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।
- **कार्यकाल:** मुख्य सूचना आयुक्त और एक सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधिया 65 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो) पद पर रह सकता है।
- वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं हैं।
- **CIC की शक्तियाँ और कार्य:**
 - आयोग का कर्तव्य है कि वह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किसी विषय पर प्राप्त शिकायतों के मामले में संबंधित व्यक्ति से पूछताछ करे।
 - आयोग उचित आधार होने पर किसी भी मामले में स्वतः संज्ञान (Suo-Moto Power) लेते हुए जाँच का आदेश दे सकता है।
 - आयोग के पास पूछताछ करने हेतु सम्मन भेजने, दस्तावेजों की आवश्यकता आदि के संबंध में सविलि कोर्ट की शक्तियाँ होती हैं।

आगे की राह

- सूचना आयोगों का उचित कामकाज लोगों को सूचना के अधिकार का एहसास कराने के लिये महत्वपूर्ण है।
 - RTI कानून के तहत **सूचना आयोग अंतिम अपीलीय प्राधिकरण** है तथा लोगों के सूचना के मौलिक अधिकार की सुरक्षा और सुविधा के लिये अनिवार्य है।
- अधिक प्रभावी और पारदर्शी तरीके से कार्य करने के लिये **पारदर्शिता प्रहरी की तत्काल आवश्यकता** है।
- डिजिटल RTI पोर्टल (वेबसाइट या मोबाइल एप) अधिक कुशल और नागरिक-अनुकूल सेवाएँ प्रदान कर सकता है जो परंपरागत मोड के माध्यम से संभव नहीं है।
 - यह पारदर्शिता चाहने वालों और सरकार दोनों के लिये फायदेमंद होगा।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न. सूचना का अधिकार अधिनियम केवल नागरिक सशक्तीकरण के बारे में नहीं है, यह अनिवार्य रूप से जवाबदेही की अवधारणा को फरि से परभाषित करता है। चर्चा कीजिये। (2018)

स्रोत: द हिंदू

भारत-आर्मेनिया संबंध

प्रलिमिंस के लिये:

आर्मेनिया की अवस्थिति

मेन्स के लिये:

भारत-आर्मेनिया संबंध

चर्चा में क्यों?

आर्मेनिया और भारत वर्ष 2022 में द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।



ऐतहासिक संबंध:

- आर्मेनिया और भारत के बीच सक्रिय राजनीतिक संबंध हैं। अंतरराष्ट्रीय नकियों के तहत दोनों देशों के बीच प्रभावी सहयोग है।
- वर्ष 1991 में आर्मेनिया की स्वतंत्रता के बाद आर्मेनिया-भारत संबंधों को फरि से स्थापति किया गया।
- वर्ष 1992 में आर्मेनिया गणराज्य और भारत के बीच राजनयिक संबंध स्थापति हुए।
- वर्ष 1999 में येरेवन में भारतीय दूतावास स्थापति किया गया।
- यदि आर्मेनिया-भारत राजनीतिक संबंधों का "उत्कृष्ट" के रूप में मूल्यांकन किया जाए, तो आर्मेनिया एकमात्र स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल (CIS) देश है, जिसके साथ भारत के वर्ष 1995 में (रूस के अलावा) राजनयिक संबंध थे।
 - CIS की स्थापना वर्ष 1991 में सोवियत संघ के वघिटन के बाद हुई थी।
 - वर्तमान में CIS में शामिल देश हैं: अज़रबैजान, आर्मेनिया, बेलारूस, कज़ाखस्तान, कर्गिज़स्तान, मोल्दोवा, रूस, ताजकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़बेकिस्तान और यूक्रेन।
- भारत और आर्मेनिया ने वर्ष 1995 में मतिरता और सहयोग पर एक संधिपर हस्ताक्षर किये।
- लेकिन दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को पर्याप्त नहीं माना जा सकता है।

दोनों देशों के बीच सहयोग के क्षेत्र:

- रक्षा संबंध:
 - आर्मेनिया ने 2020 के युद्ध से पहले ही भारतीय सैन्य उपकरण में दलिचस्पी दिखाई थी।
 - वर्ष 2020 में आर्मेनिया ने चार वपन लोकेटिंग रडार (WLR) यानी स्वात रडार की आपूर्ति के लिये भारत के साथ 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर के हथियारों के सौदे पर हस्ताक्षर किये।
 - अक्टूबर 2022 में भारत ने आर्मेनिया के साथ मसिाइल, रॉकेट और गोला-बारूद के नरियात के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये।
 - मसिाइलों में मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर स्वदेशी पनिका भी शामिल है।
 - भारत द्वारा आर्मेनिया को अपनी मैन-पोर्टेबल एंटी-टैंक गाइडेड मसिाइल (MPATGM) भी नरियात की जा सकती है।
- आपूर्ति शृंखला और अर्थव्यवस्था:
 - आर्मेनिया वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं की प्रतियोगिता में, यूरेशियन कॉरडोर, जो फारस की खाड़ी से रूस और यूरोप तक फैला हुआ है, केंद्र के लिये एक संभावित स्थान प्रदान कर सकता है।
 - आर्मेनिया कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, वनरिमाण और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में भारत की उन्नति में एक योग्य भागीदार भी साबति हो सकता है।
 - यह सहयोग ऋणगरस्त चीनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मॉडल के लिये एक उत्कृष्ट वकिल्प प्रदान कर सकता है।
 - यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि आर्मेनिया द्वारा भारतीय रक्षा हार्डवेयर की बढ़ती खरीद से अंततः भारत में सार्वजनिक और नजी क्षेत्र के रक्षा वनरिमाण दोनों को प्रोत्साहन मलिंगा।

भारत के लिये आर्मेनिया का महत्त्व:

- अखलि-तुर्कवाद का मुकाबला:

- अंकारा से प्रशासित एक अखलि-तुर्क साम्राज्य स्थापित करने की तुर्की की शाही महत्त्वाकांक्षा वर्तमान काकेशस और यूरेशिया के अन्य हसिनों में देखी जा सकती है।
- नस्लवादी सिद्धांत एक साम्राज्य की कल्पना करता है जिसमें सभी राष्ट्र और क्षेत्र शामिल होते हैं जो तुर्की भाषा बोलते हैं, उन भाषाओं और तुर्की में बोली जाने वाली भाषाओं के बीच अंतर की सीमा के साथ-साथ क्षेत्रों की संबंधित आबादी के अनुमोदन की उपेक्षा करते हैं।
- आर्मेनिया को सैन्य उपकरण के हालिया नरियात के साथ नई दलिली ने खुले तौर पर खुद को **नागोर्नो-काराबाख संघर्ष** में आर्मेनियाई पक्ष में रखा है, इसलिये भारत ने तुर्की और पाकिस्तान सहित अज़रबैजान एवं उसके समर्थकों के साथ-साथ अंकारा की वसितारवादी अखलि-तुर्की महत्त्वाकांक्षा का मुकाबला करने के लिये आर्मेनिया का पक्ष लिया है।

■ भू-सामरिक लाभ:

- एक सहयोगी के रूप में पाकिस्तान, अज़रबैजान के संघर्षों में सेना तथा सैन्य साजो-सामान की आपूर्ति करता रहा है।
- इसी प्रकार अज़रबैजान ने भी इस्लामाबाद में अपने साझेदारों को भू-राजनीतिक, भू-आर्थिक और भू-रणनीतिक लाभ प्रदान किये हैं।
- आर्मेनिया में अज़रबैजान की सफलता से पाकिस्तान अत्यधिक सक्रिय हो जाएगा जिसके घातक परिणाम हो सकते हैं।
- आर्मेनियाई क्षेत्र पर ज़बरन अधिग्रहण करने का उद्देश्य तुर्की, अज़रबैजान, पाकिस्तान तथा तुर्की-उन्मुख राष्ट्रों से लेकर चीन तक तक अबाध पहुँच हासिल करना है।
 - सैन्य साजो-सामान तथा गोला-बारूद को कश्मीर की सीमा तक पहुँचाने के लिये इस मार्ग का उपयोग किया जा सकता है।
- इसे रोकने के लिये भारत अपने सैन्य कौशल और क्षमताओं के रूप में आर्मेनिया की सहायता कर सकता है ताकि वह अज़रबैजान की सैन्य ताकत से स्वयं से सुरक्षित रख सके।

■ आर्थिक सहयोग:

- आर्मेनिया भारत समर्थित अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन कॉरिडोर (Indian-backed International North-South Transport Corridor- INSTC) और ईरान समर्थित **काला सागर-फारस की खाड़ी परिवहन कॉरिडोर** में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

आगे की राह

- आर्मेनिया-भारत सहयोग विकसित लोकतंत्रों के साथ आर्मेनिया के लिये व्यापक संपर्कों का एक अभिन्न अंग बन सकता है। इन उद्देश्यों के लिये **उच्च-गुणवत्ता और सूक्ष्म कूटनीति अनिवार्य है।**
- अंतरराष्ट्रीय संबंधों की संरचना भी बदल रही है, जिससे संभावित खतरे और अवसर दोनों पैदा हो रहे हैं।
- इन बदलते वैश्विक संबंधों के परिदृश्य में आर्मेनिया को वैश्वी संबंधों के गहरे विविधीकरण की आवश्यकता है।
- पश्चिमी देश इस दशा में महत्त्वपूर्ण अभिक्रिया बन सकते हैं।
- समान मूल्यों को साझा करके आर्मेनिया और राज्यों का समुदाय एक साथ मिलकर काम करने में सक्षम होंगे।
 - यह सहयोग का महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है जो आधुनिकीकरण के सिद्धांत, संस्थागतकरण और संभवतः राष्ट्रीय रक्षा को मज़बूत करने के सक्रिय कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

भीड़ प्रबंधन

प्रलमिस के लिये:

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005

मेन्स के लिये:

भीड़/भगदड़ आपदा के कारण

चर्चा में क्यों?

सथिल, दक्षिण कोरिया और गुजरात के मोरबी में हाल की त्रासदयों ने एक बार फिर भीड़ एवं उनके प्रबंधन को सुर्खियों में ला दिया है।

- **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority- NDMA)** को **आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005** के प्रावधानों के तहत अन्य बातों के साथ-साथ आपदाओं के प्रबंधन के लिये दशा-नरिदेश जारी करने हेतु अधिदेशित किया गया है जो समय-समय पर सामान्य जीवन व लोगों की भलाई को प्रभावित करते हैं।

भीड़ प्रबंधन:

- भीड़ प्रबंधन को व्यवस्थित योजना के रूप में परिभाषित किया गया है और लोगों की व्यवस्थित आवाजाही और जनसमूह की नगिरानी के रूप में परिभाषित किया गया है।
- भीड़ प्रबंधन में उपयोग से पहले किसी स्थान की क्षमताओं का आकलन शामिल है।
- इसमें अधिभोग के अनुमानित स्तरों का मूल्यांकन, प्रवेश और निकास के साधनों की पर्याप्तता, प्रसंस्करण प्रक्रियाएँ जैसे- टिकट संग्रह एवं अपेक्षित प्रकार की गतिविधियाँ तथा समूह व्यवहार शामिल हैं।

भीड़ आपदा/भगदड़ के कारण:

- **संरचनात्मक वफिलताएँ:**
 - अवैध संरचनाओं, फेरीवालों और पार्कगि, अंतरिम सुविधाओं, ऊर्ध्वाधर सीढ़ियों, संकीर्ण इमारतों के वधिवंस के कारण।
- **बजिली/अग्नि आपदाएँ:**
 - उत्सव के दौरान पटाखों का अनुचित उपयोग या गलत वायरिंग एक सामान्य कारण है।
 - बजिली की आपूर्ति में वफिलता से दहशत पैदा होती है और अचानक भगदड़ शुरू हो जाती है।
- **भीड़ का व्यवहार:**
 - भीड़ को कम करना, प्रबंधन के साथ समन्वय की कमी, टिकटों की अधिक बिक्री, सेलबिरिटी से ऑटोग्राफ या मुफ्त उपहार प्राप्त करने के लिये अचानक भीड़ या अफवाहों से बड़े पैमाने पर घबराहट।
 - लोगों को अपनी गतिविधियों को नयित्तरि करने के लिये कम-से-कम 1 वर्ग गज जगह की आवश्यकता होती है। भीड़ में मरने वाले ज़्यादातर लोग सीधे खड़े होने पर दम घुटने से मरते हैं, रौंदने से नहीं।
- **अपर्याप्त सुरक्षा:**
 - सुरक्षा टीमों की अपर्याप्त तैनाती के कारण ऑसू गैस के गोले दागने जैसे कठोर उपाय करना।
- **प्रशासनिक एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी:**
 - अग्निशमन सेवा, पुलिस, धर्मस्थल प्रबंधन आदिके बीच अपर्याप्त समन्वय।

भीड़ प्रबंधन संबंधी NDMA दिशा-निर्देश:

- पहला कदम पांडालों और दशहरा मैदानों के आसपास के क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को वनियिमति करना है।
 - पैदल चलने वालों के लिये कार्यक्रम स्थल तक पहुँचने हेतु रूट मैप और आपातकालीन निकास मार्ग आदिका सटीक निर्धारण किया जाना चाहिये। कतारबद्ध लोगों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिये बैरकिडिंग बढ़ती हुई भीड़ को नयित्तरि करने के लिये महत्वपूर्ण है।
- आंदोलन पर नज़र रखने के लिये सीसीटीवी कैमरे और अन्य छोटे-मोटे अपराधों के ज़ोखमि को कम करने के लिये पुलिस की मौजूदगी भी आयोजकों के एजेंडे के अंतर्गत होनी चाहिये।
- संकरे अथवा बंद (क्लॉस्टरोफोबिक) स्थानों में चकित्सा आपात संबंधी स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे में एक एम्बुलेंस और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर जीवन रक्षा में काफी सहायक हो सकते हैं।
- भगदड़ जैसी स्थितियों में लोगों को निकास मार्गों से परिचित कराने, शांत रहने और निर्देशों के पालन में मदद करनी चाहिये।
- भगदड़ की स्थिति में व्यक्तियों को एक मुक्केबाज़ की भाँति हाथ जोड़कर अपनी छाती की रक्षा करनी चाहिये और सुरक्षित स्थान की ओर बढ़ना चाहिये।
- आयोजकों को बजिली, अग्निशमन यंत्रों का अधिकृत उपयोग और सुरक्षा दिशा-निर्देशों को पूरा करने वाली अन्य व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना चाहिये।
- आसपास के अस्पतालों की एक सूची तैयार रखना मददगार हो सकती है। हल्के, सूती कपड़े पहनने जैसी साधारण सावधानियाँ और आग बुझाने के लिये सामान्य तरीकों का ज्ञान होना ज़रूरी है।

आगे की राह

- वर्तमान विश्व में भीड़ प्रबंधन सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिये, विशेषकर भारत में।
- बड़ी संख्या में वनिशकारी घटनाएँ मानवीय त्रुटि के कारण होती हैं, सक्रिय उपायों की योजना बनाकर और उन्हें लागू करके इन आपदाओं से बचा जा सकता है। इसके अलावा पछिली त्रुटियों का विश्लेषण करना व उनसे सबक लेना महत्वपूर्ण है।
- भीड़ आपदा समाज में हर किसी के लिये चर्चा का विषय है। नेतृत्व करने में सरकार की ज़िम्मेदारी के बावजूद भविष्य में ऐसी आपदाओं को रोकने में आम जनता की भी प्रमुख भूमिका होनी चाहिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA.) के सुझावों के संदर्भ में उत्तराखंड के अनेक स्थानों पर हाल ही में बादल फटने की घटनाओं के प्रभाव को कम करने के लिये अपनाए जाने वाले उपायों पर चर्चा कीजिये। (मैन्स- 2016)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/news-analysis/30-12-2022/print>

